क्या भाजपा हिटलर की राह पर –

संजय तिवारी, विस्फोट डाट काम, दिल्ली

जब हिटलर का आखिरी वक्त आया तो उसके प्रोपेगेण्डा मिनिस्टर सैफ गोयबल्स के सामने भाग जाने या शहीद हो जाने के दो रास्ते थे। गोयबेल्स ने शहीद होने का रास्ता चुना और अपने छ बच्चो को जहर का इन्जेक्शन दिलवाने के बाद खुद को गोली मार ली थी, और उसकी पत्नी ने जहर खा लिया था। उसकी मौत के दिन 1 मई 1945 को उससे जिस की आखिरी मुलाकर हुई थी उस जनरल सें गोयेबेल्स ने साफ कहा था कि मै उस डूबते जहाज को नही छोड सकता जिसका मै कैप्टन रहा हूँ। बाकी जनरल अपनी जान बचाकर बंकरो को खाली कर गये लेकिन गोयबेल्स ने यहा भी अपने फयूहरर को अपना आदर्श रखा और हिटलर की मौत के अगले दिन अपने लिये भी मौत का ही रास्ता चुना। मौत के अडसठ साल बाद एक बार फिर गोयबेल्स जिन्दा हो चुका है। जर्मनी मे नही बल्कि एक बेहद लोकतांत्रिक तरीके के देश भारत मे। गोयबेल्स को जिंदा किया है एक और गोयबेल्स ने।

हिटलर के जर्मन राष्टवाद का खुला समर्थन करने वाली भारत की दक्षिणपंथी पार्टियो मे सबसे बडी भारतीय जनता पार्टी बीते कुछ महीनो से सही मायनो मे हिटलरवादी विकल्प लेकर पूरे देश मे धूम रही है। वैचारिक रूप से उसका समाजवादी राष्टवाद अटल विहारी की बीमारी के साथ ही अधमरा हो गया और एक नये तरह के पूंजीवादी कारपोरेट राष्टवाद ने उस गुजरात से जन्म लिया है जो कभी समाजवाद के आदर्श गांधी का गुजरात हुआ करता था। यह नये तरह का राष्टवाद सिर्फ सख्त ही नही बल्कि असहिष्णु भी है, अवसरवादी भी। इन नये तरह के कठोर राष्टवाद का नायक भी जाहिर तौर पर कटटर कठोर और जिददी छवि रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो बीते दस सालो से अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री है। उस मुख्य मंत्री के समर्थक और प्रशंसक उसके अंदर वही राष्टवादी नायक की छवि देखते है, जो जर्मनी मे नाजी समर्थक हिटलर मे देख पाते थे। किसी वर्ग विशेष का हत्याकांड और दमन ही एक ऐसा मुददा नही है जिसके आधार पर दोनो नायको की छवियां अगल बगल रख ली जाये । इसके अलावा भी बहुत सी बाते ऐसी है जो उन्हे अपने कटटर समर्थको की नजरो मे राष्टनायक सा दर्जा देती है।

मजबूत अर्थ व्यवस्था व्यापार तंत्र, सख्त प्रशासन, सांस्कृतिक कटटरता और आंतरिक लोकतंत्र का खातमा कुछ ऐसे अन्य पहलू है जो किसी हिटलर के होने से ही संभव है। हिटलर का उभार जर्मनी के जिस गर्त से हुआ था, उस वक्त वह जर्मनी की स्वाभाविक जरूरत बन गया था। उस वक्त जर्मनी को भी कोई ऐसा नायक चाहिये था जो युद्ध की जीत हार से डूबते उतरते जर्मनी की आंतरिक दशा भी सुधार देता और उस नस्लीय सम्मान को दुनिया के साथ प्रस्तुत करता कि दुनिया अदब से जर्मनी का नाम लेती । हिटलर के प्रति जर्मनी की मोहब्बत के मूल मे यही दो बाते थी और इसी मोहब्बत ने सिर्फ जर्मनी को एडोल्फ हिटलर नही दिया बल्कि दुनिया को शासन का एक नया तरीका भी दे दिया। तानाशाही राजवंशो के खत्म होते अस्तित्व, धर्म संस्थानो के टूटते किलों के बीच से कोई लोकतंत्र जैसी बात बाहर निकल आयी थी लेकिन जिनकी बिलो से लोकतंत्र का चूहा बाहर आया था वे खुद उस दौर के इराक और अफगानिस्तान बनते जा रहे थे। इसलिये अपने ही उपर शासन न कर पाने की अपनी नाकामियों और दूसरो के अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप के बीच तानाशाही एक ऐसा रास्ता था जो अफीम से भी बडा नशा बन गया था । वह नशा जब तब जहां तहां लोकतंत्र की नाकामियों का विकल्प बनाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है । भारत एक बार फिर इसी दौर से गुजर रहा है।

आपने पैसठ साल से लोकतांत्रिक सफर मे भारत मे यह पहला मौका नही है जब सख्त प्रशासन की मांग इतनी तेज हो गई है कि लोक तांत्रिक तरीको को तिलांजली देनेवाले तर्को की बाढ आ गई हैं। इंदिरा गांधी की इमरजेंसी और वी पी सिंह का उभार इसी छटपटाहट से पैदा हुआ था । एक बार फिर वही छटपटाहट चारो तरफ दिख रही है जब देश के लोग अपने ही शासको की नीति की जंजीरो मे कैद नजर आ रहे है । भ्रष्टाचार मंहगाई और कुप्रशासन जैसे लंबी अवधि के मुददे उफान पर है और उस उफान पर दो अलग अलग लोग अलग तरीके से अपनी सवारी कर रहे । एक तरफ स्थापित राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और उसके स्वाभाविक नायक नरेन्द्र मोदी है तो दूसरे तरफ बीते तीन सालो मे सतह पर आये अरविन्द्र केजरीवाल और उनकी टुटपुंजियां टीम है। क्योकि इन सभी समस्याओ की जड हमेशा की तरह एक बार फिर कांग्रेस है। इसलिये टुटपुंजिया केजरीवाल और संगठित नरेन्द्र मोदी दोनो का राजनीतिक दुश्मन साझा है। बीते कुछ महीनो मे देश भर मे नरेन्द्र मोदी ने भी उसी कांग्रेस को हर समस्या का जिम्मेदार बताया है, जिस समस्या के खिलाफ चलाई गई मुहिम के कारण अरविन्द केजरीवाल और उनकी टुंटपुजिया टीम का जन्म हुआ है। साझे दुश्मन की इस राजनीतिक मजबूरी ने अब इन दोनो को आमने सामने खडा कर दिया है।

ठीक आम चुनाव के पहले परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मरने के लिये राजनीति का रावण एक है लेकिन मारने के लिये दो दो राम तीर कमान लेकर मैदान मे पहुंच गये है। अब दोनो राम आपस मे लड रहे है कि आखिरकार रावण वध करेगा कौन ? दिल्ली मे विधान सभा चुनाव मे भाजपा का दिग्विजयी रथ रोककर टीम केजरीवाल ने संकेत दे दिया कि राजनीतिक रावण को मारने के लिये वह भी जनता का विकल्प बनकर उभर रही है। दिल्ली की टीम अरविन्द की सफलता के साथ दूसरे रामदल ने तौर कमान का मुख रावण कीतरफ से हटाकर उस रामदल की तरफ कर दिया जो जबरन रामलीला मैदान मे घुस आया था। दिल्ली विधान सभा चुनाव से लेकर आम चुनाव के बीच अब तक कई मौके ऐसे आ चुके है जब दोनो रामदल आमने सामने खडे हो चुके है। राजनीतिक रावण को मारने के लिये बनाये गये दोनो रामादलो की कमोवेश प्रचार तंत्र और राजनीतिक आक्रामकता एक जैसी है। इसलिये सोशल मीडिया से लेकर सडक तक दोनो रावण वध से पहले एक दूसरे को निपटाने में लग गये हैं।

निपटने निपटाने की इसी कडी मे भाजपा के नेता अरूण जेटली ने एक बयान दे दिया जो भाजपाई रामादल की खीझ को भी सामने लाता है और उसके राजनीतिक चरित्र पर भी सवाल खडा करता है। मीडिया से बात करते हुए अरूण जेटली ने आम आदमी पार्टी के प्रचार तंत्र की तुलना उस गोयबेल्स से कर दी है जो हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था। अरविन्द केजरीवाल के गुजरात दौरे से उपजी असहज परिस्थितियों मे अरूण जेटली की यह खीज इतनी अधिक हो जायेगी कि भारत के लोकतंत्र मे हिटलर का जिक्र शुरू कर देंगे यह थोडा सा ही सही लेकिन आपतिजनक तो है ही। कौन नही जानता कि पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर नरेन्द्र मोदी गोयबेल्स की तर्ज पर किये गये उसी प्रचार तंत्र का नतीजा हैं। जिसका दोष अब वे आम आदमी पाटी पर मढ रहे है। और इस प्रचार तंत्र की मुहिम का मुखिया कौन है? कम लोग जानते होंगे कि दिल्ली मे मोदी के प्रचारतंत्र की कमान किसी और के नही बल्कि अरूण जेटली के हाथ मे है । तो इस लिहाज से खुद जेटली ही गोयबेल्स की भूमिका मे खडे नजर आ रहे है। तो क्या उन्होने टीम केजरीवाल के लिये जिस गोयबेल्स के मुहावरे का इस्तेमाल किया वह सिर्फ इसलिये क्योकि वे खुद उसी तरह के प्रचार तंत्र का इस्तेमाल कर रहे है।

शायद हां। गुजरात विधान सभा चुनाव के बाद से सोशल मीडिया पर मोदी के उभार से लेकर आम चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले तक मोदी के प्रचारतंत्र ने अरूण जेटली और अमीत शाह की अगुवाई मे बिल्कुल गोयबेल्स की तर्ज पर काम किया है। अपने इसी प्रचारतंत्र की बदौलत एक कटटर राष्टवादी पार्टी ने एक कठोर नायक के साथ मिलकर एक राजनीति और नेतृत्व का एक ऐसा विकल्प गढ लिया है जिसमे पाटी के स्तर पर नाजीवादी तानाशाही भी नजर आती है और नेता के नाम मे हिटलरशाही भी। इस संगठित प्रचार तंत्र ने एक लोकतांत्रिक तरीको से तानाशाही को भी स्वीकार कर लेने की मनोदशा पैदा करने मे कामयावी हासिल कर ली है। जाहिर है अब कोई केजरीवाल अगर इस प्रचारतंत्र का भांडा फोडेगा तो स्वाभाविक है हिन्दूवादी गोयबेल्स को वह गोयबेल्स ही नजर आयेगा।

उत्तर– आपने बहुत ही संतुलित लेख लिखा है। मै आपको धन्यवाद देता हूँ । इस लेख पर मुझे कोई टिप्पणी नही करनी चाहिये। किन्तु स्वभाव वश मै कुछ थोडा सा लिख रहा हूँ। तानाशाही करने वालो या उनके समर्थको का परिणाम इतिहास मे कई जगहो पर दर्ज है। तानाशाह प्रायः अपने शासन काल मे बहुत लोक प्रिय हुआ करते है किन्तु उनकी लाश गिरते ही उनकी लोकप्रियता पलट जाती है। यही सददाम का हुआ गददाफी का हुआ । हिटलर का हुआ । और यही हाल रूस के तानाशाहो का भी इतिहास मे दर्ज है। तानाशाही के प्रशंसक भी इस चपेट मे आ जाते है। सुभाष चंद्र बोस गांधी की अपेक्षा अधिक देश भक्त थे किन्तु उनका अंत गांधी की अपेक्षा अधिक कष्टकारी था। सुभाष चंद्र बोस का आज भी सम्मान पूरे भारत मे है। किन्तु यदि वे भारत पर शासन करते तब उनके अंत की कसौटी क्या होती यह पता नही। उम्मीद है कि नरेन्द्र मोदी वैसी भूल नही करेंगे। और यदि करेंगे तो उस समय की परिस्थितियां उनका आकलन करेंगी। मोदी व्यक्तिगत रूप से तानाशाह नही दिखते । संध परिवार भी अलग से तानाशाह नही दिखता। किन्तु जब दोनो एक हो जाते है तब तानाशाही की गंध आने लगती है। संभव है और उम्मीद भी करनी चाहिये कि प्रधान मंत्री बनने के बाद भी मोदी के माध्यम से संघ परिवार की यह इच्छा पूरी न हो ।

> आपने कांग्रेस को रावण की संज्ञा दी । यह संज्ञा कुछ अधिक कठोर लगती है। अब तो ऐसा लगता है कि इस युद्ध मे कहीं कांग्रेस और अरविन्द केजरीवाल एक न हो जाये। आपने अरूण जेटली के विषय मे जो कुछ कहा वह सही ही है। वास्तव मे अरूण जेटली का वैसा चरित्र नही है बल्कि वे तो सिर्फ संघ परिवार के प्रवक्ता मात्र है। अब भाजपा लिखने का कोई अर्थ नही है। क्योकि भाजपा तो अब नाम के लिये ही हैं और अंतिम सांस गिन रही है। सारी कमान तो संघ परिवार के हाथ मे है। आपने अरविन्द केजरीवाल के सोलह सवालो का जिक्र किया है।

उनमे से एक सवाल ही मोदी जी को परेशान कर रहा है कि अम्बानी परिवार से उनके संबंध क्या है? मोदी जी का सारा खर्च अम्बानी उठा रहे है या नही ? प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी जी अम्बानी की गैस की कीमत कितनी रखेंगे आदि। मै समझता हूँ कि ये सब सवाल एक ही सवाल के साथ जुडे है जिनका उत्तर न मोदी के पास है न संघ परिवारके पास और न भाजपा के पास। यही प्रश्न मोदी जी को बहुत परेशान कर रहा हैं ।

पत्रोत्तर

1 प्रश्न– ओम प्रकाश मंजुल पिलीभित उत्तर प्रदेश

प्रश्न– आपने ज्ञान तत्व 285 मे मेरे प्रश्नो का उत्तर दिया। आपने लिखा कि मै मोदी की ओर एक पक्षीय झुका हुआ हूं और तटस्थता से दूर हो जाता हूँ । मुझे ऐसा लगता है कि आप अरविन्द केजरीवाल की ओर अधिक झुके हुए है और तटस्थ नही रह पाते है। मेरे विषय मे आपने जो लिखा है उसके साथ ही आप अपने झुकाव को भी स्पष्ट करे।

उत्तर– आपने जो मेरे विषय मे लिखा है वह सही है। मै अरविन्द केजरीवाल की ओर झुका हुआ हूँ और ऐसी स्थिति मे पूरी तरह तटस्थ नही रह पाता हूँ । नीति बताती है कि आलोचना विरोधी और शत्रु के संबंध मे तटस्थता की मात्रा भिन्न भिन्न हो जाया करती है। मेरा जो झुकाव है, वह किसी भी रूप मे व्यक्तिगत न होकर नीतिगत है। आज से पांच वर्ष पहले जब देश मे अरविन्द केजरीवाल नही दिखते थे तो मै कांगेंस पार्टी की अपेक्षा नरेन्द्र मोदी को अच्छे प्रधान मंत्री के रूप मे देखता था। मै ने एक सूची प्रकाशित की थी जिसमे अच्छे लोगो के नाम थे उसमे मनमोहन सिंह नीतिश कुमार नरेन्द्र मोदी रमण सिंह शिव राज सिंह चौहान पृथ्वी राज चौहान बुद्ध देव भटटाचार्य केरल के उस समय के मुख्यमंत्री अच्युता नंदन शान्ता कुमार बाबु लाल मरांडी आदि के नाम थे। इस सबको मै अच्छे लोगो की सूची मे मानता था। एक दूसरी सूची भी बताती थी जिसमे अजीत जोगी राम विलास पासवान लालू प्रसाद, मायावती, मुलायम सिंह, सिबु सोरेन, जय ललिता, करूणा नीधि, ममता बनर्जी जैसे के नाम थे। इन सबको मै व्यक्तिगत रूप से अच्छा नही मानता था। यह सूची ज्ञान तत्व मे कई बार प्रकाशित हुई है। और आप चाहेंगे तो भेज दूंगा। मै आज भी अपनी उस सूचि पर कायम हूँ । उस सूची मे मैने स्पष्ट लिखा था कि प्रधान मंत्री पद के लिये सबसे अच्छे उमीदवार मनमोहन सिंह है। दूसरे क्रम मे नीतिश कुमार आते है और तीसरे क्रम मे नरेन्द्र मोदी है। मैने जो क्रम बनाया था उसमे मैने यह भी लिखा था कि यदि नेहरू परिवार का कोई व्यक्ति प्रधान मंत्री पद का दावेदार होता है तो उसमे चाहे जितने भी गुण हों, उसे पूरी ताकत से हरा देना चाहिये। भले ही उसके स्थान पर कैसे भी कोई व्यक्ति क्यो न आ जाये। मै स्पष्ट करूं कि आज भी मै अपनी बात पर कायम हूँ क्योकि मेरा कथन नीतियो पर आधारित था न कि व्यक्तिगत भावनाओ पर ।

जब अरविन्द केजरीवाल का उदय हुआ तो मैने अरविन्द केजरीवाल को प्रधान मंत्री पद के लिये तीसरे नम्बर पर डाला अर्थात मोदी से उपर । मै अब्यवस्था को खराब मानता हूँ और लोक स्वराज्य को अच्छा । मनमोहन सिंह सबसे अधिक विकेन्द्रीयकरण की दिशा मे बढ रहे थे। और नीतिश कुमार दूसरे नम्बर पर थे। इसलिये मै इन दोनो को उपर मानता था। अरविन्द केजरीवाल भी विकेन्द्रीयकरण की दिशा मे बढने लगे तो मै उन्हे भी महत्वपूर्ण मानने लगा और यदि वे तीनो ही समाज के द्वारा अस्वीकृत हो जाते है तो देश लोक स्वराज्य की दिशा मे भी नही बढेगा, और स्वशासन भी नही आयेगा। वह स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होगी। अव्यवस्था या तो स्वशासन से दूर हो सकती है अथवा तानाशाही से। स्वशासन हो तो उसके लिये मै सर्वोच्च प्राथमिकता मानता हूँ और यदि संभव न हो तो तानाशाही को भी स्वीकार कर सकता हूँ किन्तु अव्यवस्था को नही । इसलिये मैने नरेन्द्र मोदी को चौथे नम्बर पर रखा। वर्तमान स्थिति मे मनमोहन सिंह की संभावना शून्य हो चुकी है, नीतिश कुमार भाग्य भरोसे है, अरविन्द केजरीवाल की संभावना कुछ बनी हुई है, और नरेन्द्र मोदी तो निश्चित हैं ही। ऐसी स्थिति मे अरविन्द केजरीवाल मे लोक स्वराज्य की संभावना देखते हुए मै तानाशही का समर्थन क्यो करूं । मैने नरेन्द्र मोदी की जगह सिर्फ अरविन्द केजरीवाल या नीतिश कुमार का ही समर्थन किया है, किसी और का नही। मैने तो यहां तक भी लिखा है कि औरो की अपेक्षा तो नरेन्द्र मोदी ही अच्छे है और राहुल गांधी की अपेक्षा चाहे जो भी हो, स्वीकार किया जा सकता है । चाहे वह कैसा भी है । अब मेरे सामने यह संकट अवश्य है कि लोक स्वराज्य के लिये मै अरविन्द केजरीवाल के पक्ष मे हूँ इसके लिये यदि आप मुझे निष्पक्ष न समझे तो मै क्या कर सकता हूँ । यदि नीतिगत आधार पर आप नरेन्द्र मोदी के पक्ष मे कुछ लिखेगे तो मै विचार करूंगा । किन्तु भावनात्मक रूप से यदि आप किसी का पक्ष लेते है

तो वह पक्षपात सामान्य लोगो के लिये तो उचित हो सकता है किन्तु आपके लिये नही, क्योकि आपकी गिनती सामान्य लोगो मे नही है।

2 शिव दत्त बाघा बांदा उत्तर प्रदेश ज्ञान तत्व कमांक 7880

फरवरी 1 से 15 ज्ञान तत्व मे समाजवाद की मनमानी व्याख्या की गयी है । दर असल समाजवाद का अर्थ होता है कि यह शरीर भी समाज का यानी समाज के प्रति व्यक्ति का समर्पण ।

तू ने दिया यह तेरा है, तेरा तुझको सौपते क्या? लोग है मोर । जब इस धरती मे मेरा कुछ है ही नही, सब तेरा ही है , यानी समाज का तब फिर यह देह भी तेरी ही है। ऐसा भाव ही समाजवाद है। धरती मे जीने के जो भी संसाधन है उसमे किसी एक व्यक्ति एक समूह अथवा जाति का नही वरन पूरे समाज का हक है। ऐसा भाव ही समाजवाद है। समाजवाद राष्टवाद मे कोई मौलिक भेद नही है। सिवाय आकार के। परिवार गांव जनपद राज्य राष्ट मे विभाजन समाजवाद का गुण धर्म स्वभाव नही हो सकता। मानव से मानव का अलगाव , फिर संसाधनो का बटवारा एकाधिकारी प्रवृत्ति है, न कि समाजवादीं।

मछली का जीवन पानी है तो मनुष्य का जीवन समाज है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ही नही हिंसक व विषैले जीवो को अपवाद मे ले तो समस्त प्राणी सामाजिक है। विषैले जीवो मे भी यह अपवाद है कि वर्र व मधुमक्खियो जैसे अनेक जीव समूह समाज के होकर जीते है और इनकी सारी गतिविधियां अपने समाज को समर्पित होती है। वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा ही समाजवाद है।

उत्तर– यह बात सही है कि प्रत्येक विचारक भूतकाल मे प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षो पर चिंतन करता है और देश काल परिस्थिति के अनुसार उनकी समीक्षा करके उनमे संशोधन भी करता है। समाजवाद की पुराने समय मे प्रचलित परिभाषा मे पूंजीवादी प्रभाव के समय साम्यवादियों ने अपने ढंग से संशोधन करके जो परिभाषा बनायी वह हो सकता है कि उस समय ठीक हो और आज गलत हो गयी हो । मै एक विचारक हूँ और मैने उस की परिभाषा की समीक्षा करके उसे संशोधित रूप मे प्रस्तुत किया है। आपने अपने ढंग से उसकी परिभाषा बनायी है किन्तु यदि आप ज्ञान तत्व के उस अंक मे दी गयी परिभाषा मे संशोधन का आधार भी बताते तो अधिक अच्छा होता।

आपने समाज की जो परिभाषा दी है उसके अनुसार समाज का अर्थ होता है, व्यक्ति का समाज के प्रति समर्पण। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति समाज की स्वतंत्र इकाई ना होकर उसका एक अंग होगा । मैरे विचार से व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है जो स्वतंत्र होते हुए भी परिवार, गांव, जिला, प्रदेश, देश और विश्व समाज के साथ जुडा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि समाज आवश्यक होते हुए भी व्यक्ति के मूल अधिकारो मे कटौती नही कर सकता। अर्थात यदि समाज को किसी व्यक्ति की जान की आवश्यकता है तो वह व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी जान नही ले सकता। मूल अधिकारो पर आक्रमण कोई सरकार भी कभी कर ही नही सकती। सारा विश्व भी कभी नही कर सकता, जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारो पर आक्रमण ना किया हो । बहुत प्राचीन समय मे भारतीय समाज मे यह अवधारणा थी कि समाज किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के दण्ड नही दे सकता था। इस्लामिक काल मे भारत मे इस्लामिक अवधारणा थोपी गयी कि समाज किसी व्यक्ति को संगसार तक अर्थात मृत्यु दण्ड तक दे सकता है। यह गलत अवधारणा थी और धीरे धीरे पश्चिमी जगत ने इस अवधारणा को गलत सिद्ध किया। किन्तु पश्चिमी जगत ने एक भूल कर दी कि उसने सामाजिक बहिष्कार जैसी ठीक अवधारणा को भी अमान्य कर दिया। इस अवधारणा परिवर्तन का दुष्प्रभाव हुआ और साम्यवाद ने उसमे संशोधन करके राज्य को ही समाज घोषित कर दिया जिसके अनुसार समाज का कोई अस्तित्व नही रहा। आप जो समाज की परिभाषा लिख रहे है वह ईस्लामिक परिभाषा है। जिसके अनुसार धर्म और समाज एक हो जाते है और व्यक्ति का अस्तित्व नही रहता । आपकी परिभाषा साम्यवाद से भी मिलती जुलती है जिसमे राज्य ही समाज है और व्यक्ति का कोई अस्तित्व नही है। मेरी परिभाषा ईस्लामिक और साम्यवाद से भिन्न है तथा पश्चिमी जगत की परिभाषा का संशोधित स्वरूप है अर्थात समाज परिवार का एक अंग है । गांव परिवारो का समूह है । जिला गांवो का समूह है। प्रदेश जिलो का

समूह है देश या राष्ट्र प्रदेशो का समूह है तथा समाज राष्टो का समूह है। इसके साथ ही समाज व्यक्तियो का संघ भी है तथा इन ईकाइयों का भी अंग है। मै समझता हूँ कि इस स्पष्टता पर आप विचार करेंगे।

3 डा0 रामतीर्थ अग्रवाल दिल्ली ज्ञान तत्व कमांक18789

प्रश्न– ज्ञानतत्व नियमित मिलता है, आभारी हूँ। जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की बात कहना सिर्फ बात तक ही सीमित रहने वाली बात है। राहुल जी के प्रसंग को देंखें। इन्हें इतना भी पता नही है कि कच्छी पहनी है या पैन्ट पहनी है। आरक्षण को (जातिगत) बढाकर इन्हें वोट मिलती है तो ये आरक्षण को बढा देंगें और समाप्त करके इन्हें वोट मिलती है तो ये समाप्त कर देंगें। इनकी सारी राजनीति कुर्सी तक केन्द्रित है। केजरीवाल से लोंगों का बुरी तरह से मोह भंग हुआ है। चूँकि बात में से बात निकाल कर बात करने में ये महाशय दक्ष जरूर हो सकते हैं, लेकिन करने धरने के नाम पर जीरो साबित हुआ है। फिर भी जनता में इनके लिय मोह बाकी है। इसलिए इन्हें वोट काटू पार्टी कहा जा रहा है। मोदी जी की प्रतिष्ठा दिनों–दिन बढ रही है। लेकिन हमारे देश में अराष्टीय लोगों का कुनबा बहुत बडा है जो हर स्तर पर मोदी को काट रहा है। वैचारिक दृष्टि से मोदी जी का व्यक्तित्व किसी के लिए भी अहितकर नही है। बात वो कही जानी चाहिए जिससे देश का भला हो। मैं निजी स्तर पर यह कहने का पक्षधर रहा हूँ कि देश को चलाने के लिए नया संविधान लिखा जाना चाहिए, लेकिन समाज इस बात को सुनने के लिए तैयार नही है। विचार अच्छा लगे तो उपयोग करें।

उत्तर– मै नही कह सकता कि राहुल गांधी राजनैतिक स्वार्थ के कारण जातीय आरक्षण के विरूद्ध सोच रहे है अथवा आज की आवश्यकता समझकर । मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी जो कुछ करना चाहते है उसमे कुछ सच्चाई है, किन्तु चुनाव नजदीक होने के कारण उस कथन का चुनावो पर विपरीत असर पडता है । ऐसे गंभीर विषय पर जो राहुल गांधी ने मुजफरनगर मे कहा अथवा आरक्षण पर जो संकेत दिया वह चुनाव के समय कहना उनकी राजनैतिक अदूरदर्शिता मानी जायेगी। यही कारण है कि बात सही होते हुए भी उन्हे वह बात कहने से रोक दिया गया। जहां तक अरविन्द केजरीवाल का संबंध है उनके विषय मे इतना स्पष्ट है कि चुनावो के परिणाम घोषित होने के बाद उनके पक्ष मे एकाएक जो बाढ आयी थी वह बाढ उतर गयी है और उस बाढ के प्रभाव मे आये लोगो का मोह भंग हुआ है । उसके पूर्व के लोंगो का मोह वैसा ही है और कुछ ना कुछ उनका प्रभाव बढा ही है। नमो की जो आंधी चल रही है वह स्पष्ट है। आप भी देख रहे है और मै भी देख रहा हूँ । मै यह मानता हूँ कि अराष्टीय लोगो का एक कुनबा बढा है जो मोदी को काट रहा है किन्तु यह तो सोचना उचित है कि वर्तमान समय मे वर्तमान अव्यवस्था का एक मात्र विकल्प मोदी है किन्तु लोक स्वराज्य की अवधारणा मोदी से भी अच्छी अवधारणा है जिसे बढाने मे अन्ना हजारे और अरविन्द केजरीवाल कुछ अपनी गलतियों के कारण सफल नही हो सके। अन्यथा जो आंधी मोदी की दिख रही है वही आंधी मोदी के विरूद्ध अन्ना अरविन्द की दिखती । मोदी जी की आंधी एक समाधान तो है किन्तु सतर्कता का खतरा भी है कि कही वह हिटलर शाही मे ना बदल जायें । इसलिये अन्ना हजारे अरविन्द केजरीवाल के असफल होने के बाद भी उस अवधारणा को जीवित रखने की अवश्यकता हैं । इसी सोच के अतर्गत लोक स्वराज्य मंच तथा व्यवस्था परिवर्तन मंच ने सामूहिक रूप से आगे बढने का काम किया है। अर्थात दिनांक 13 जुन से 22 जून तक जंतर मंतर पर दिल्ली मे धरना देने का कार्यक्रम बनाया है जिसकी विस्तृत जानकारी इसी अंक के अंत मे दी गयी है। इस धरने के कार्यक्रम मे संविधान संशोधन की बात भी शामिल है।

4 चिन्मय व्यास मालदेवता देहरादून उत्तराखंड ज्ञान तत्व कमांक 1826

प्रश्न– आगामी आम चुनाव मे ऐसी स्थिति आ सकती है कि किसी दल या गठ बंधन को स्पष्ट बहुमत न मिले और राष्ट्र पति शासन की जरूरत पडे। फिर भी चुनाव के समय ज्ञान तत्व क्या करे इस दृष्टि मे हमे जनता के सामने कुछ मार्ग दर्शक बाते रखनी चाहिये। संसद मे गलत किस्म के लोग न पहुंचे । चाहे वे किसी भी दल के हो । यदि अच्छे आचरण वाले समझदार लोग संसद मे पहुंचेगे तो देश का कुछ भला होगा। यदि ज्यादा समझदार सांसद चुने गये तो वे संसद पर किसी प्रकार का सामाजिक नियंत्रण अर्थात लोक संसद की बात सोच सकते है । हम जनता से अपील कर सकते है कि वे

1 किसी भी ऐसे व्यक्ति को न चुने जो चुनाव के लिये ज्यादा खर्च करता है क्योकि जो ज्यादा खर्च करता है वह चुने जाने पर ज्यादा कमाई करेगा चाहे वह किसी दल का हो।

2 व्यक्ति का चरित्र, आचरण और सेवा भावना देख कर उसे चुने, दल देख कर नही।

3 चुने जाने पर जो व्यक्ति अपनी आय और व्यय का वार्षिक हिसाब जनता के समक्ष प्रस्तुत करने का वादा करता हो उसे चुने । साथ ही यह भी वादा करे कि यदि मेरे क्षेत्र की जनता को मेरे कार्य से व्यापक असंतोष हुआ तो मै अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा।

4 जो उम्मीदवार बडे बडे वादे करे, आपको लालच दे, मुफत मे वस्तुए बाटे, पैसे बाटे, धमकी दे या इस तरह के गलत काम करे उसे वोट कदापि न दे क्योकि जो व्यक्ति भी गलत काम कर रहा है वह चुने जाने के बाद भी गलत काम करता रहेगा । संसद का समय बर्बाद नही करे । संसदीय अनुशासन का पालन करने का वादा करे।

इसी तरह की कुछ बाते मार्ग दर्शक सिद्धान्त के रूप मे हमारे द्वारा आम जनता के सामने रखी जानी चाहिये।

आम चुनाव के नतीजे तक हमे जनसंसद की बात स्थगित रखनी चाहिये और लोक शिक्षण पर ज्यादा ध्यान देना चाहिये।

यदि आपकी दृष्टि मे कुछ ऐसे नाम हो जिनका संसद मे पहुंचना देश के लिये हितकर होगा तो उनके नाम आप अपनी पत्रिका मे छापिये । फिर वे चाहे किसी भी दल के हो या प्रत्यक्ष राजनीति से दूर हो। उदाहरण के लिये– 1 किरण बेदी 2 मेघा पाटकर 3 जनरल वी के सिंह 4 जयराम रमेश 5 ए के एंटनी 6 सुषमा स्वराज जैसे कई नाम जोडे जा सकते है

हमारे देश की राजनीति और शासन प्रणाली मे अनुशासन की सख्त जरूरत है। इसलिये संसद मे कुछ अच्छे रिटायर्ड सेनाधिकारी, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, न्यायाधीश चुने जावे तो कम से कम संसद मे ऐसे वीभत्स दृष्य और उच्श्रृखता तो नही दिखेगी । ये सब तात्कालिक उपाय है ताकि संसद मे ज्यादा विकृति न बढे।

उत्तर– आपने पूछा है कि इस चुनाव के लिये हम क्या करे? वास्तविकता यह है कि पहली बार हम स्पष्ट निर्णय करने मे अपने को असफल पा रहे है। जो वर्तमान स्थिति है उसमे अव्यवस्था है और इससे मुक्त होने के दो ही मार्ग है। एक तानाशाही दूसरा लोक स्वराज्य । अन्ना हजारे अरविन्द केजरीवाल की टीम असफल होने के बाद लोक स्वराज्य का मार्ग धुंधला हो गया है तो जनता दूसरे विकल्प अर्थात तानाशाही की ओर झुक गयी है। तीसरा मार्ग अभी दिख नही रहा । ऐसी स्थिति मे मुझे ऐसा दिखता है कि वर्तमान चुनाव मे जहां अरविन्द केजरीवाल की टीम दूसरे नम्बर पर या पहले नम्बर पर दिखती हो वहां उनकी ताकत मजबूत करनी चाहिये। लेकिन जहां अरविन्द केजरीवाल की टीम कमजोर हो वहा किसी अच्छे व्यक्ति को जिताने का प्रयास करना चाहिये । यदि ऐसा व्यक्ति लोक स्वराज्य या लोक संसद समर्थक हो तो ज्यादा अच्छा है। ऐसे ही एक व्यक्ति हरियाणा से अपना पुलिस आई जी का पद छोडकर कुरूक्षेत्र हरियाणा से लोक सभा उम्मीदवार है, जिनका नाम रणवीर शर्मा है। ऐसे व्यक्ति और जहां भी हो उनका समर्थन किया जा सकता है।

आपने अच्छे व्यक्तियो को राजनीति मे आगे बढाने के सिद्धान्त का समर्थन किया है । यह कोई आदर्श स्थिति नही है। कार्यपालिका के लिये तो चरित्र की अनिवार्यता है किन्तु विधायिका के लिये नही। वर्तमान समय मे आपको चरित्र इसलिये आवश्यक दिख रहा है क्योकि विधायिका ने कार्यपालिका के अधिकार भी अपने पास समेट लिये है। अच्छा तो यह होता कि चरित्र चरित्र की रट लगाने की अपेक्षा कार्यपालिका और विधायिका को अलग अलग किया जाता और कार्यपालिका के जो अधिकार विधायिका ने छीन लिये है वे उसे वापस दिये जाते । उससे भी अच्छा ये होता कि चुनाव नीतियों के आधार पर लडे जाते और प्रत्येक उम्मीदवार अपने अपने विधायी सोच का खाका चुनाव पूर्व प्रस्तुत करता किन्तु ऐसा नही होता।

आपने जन संसद की बात स्थगित करने को कहा है तो वह तो स्थगित है ही। उसके लिये तो चुनाव के बाद चाहे किसी की सरकार बने इस बात की परवाह किये बिना 13 जून से 22 जून 2014 तक जंतर मंतर दिल्ली पर एक धरना देने की योजना है। आप सब उसमे आमंत्रित है। आपने जो 6 नाम बताये है उनमे से ऐसा कौन सा नाम है जो सत्ता के अकेन्द्रिय करण या विकेन्द्रीयकरण की योजना के अंतर्गत चुनाव लड रहा हो । किरण बेदी और जनरल वी के सिंह तो स्पष्ट रूप से केन्द्रीयकरण या तानाशाही के पक्षधर हो गये है। सुषमा स्वराज्य वहां मजबूरी है। मेधा पाटकर इस मामले मे साफ नही है। जयराम रमेश और एंटोनी सोनिया के गिरोह के अहम सदस्य है। जब ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बात कह नही सकते तो हम किसको अच्छा माने और किसको बुरा। इसलिये हम व्यक्तियो पर ज्यादा ध्यान न देकर नीतियों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं ।

5 श्याम नारायण श्रीवास्तव रायगढ छत्तीसगढ ज्ञान तत्व कमांक 14278

प्रश्न– पत्रिका ज्ञान तत्व नियमित प्राप्त हो रही है। राजनीति व समाज मे हो रहे तमाम उथल पुथल पर आपकी सार्थक टिप्पणी सदैव पठनीय है।

चाहता हूँ कि एक बहस इस पर भी छिडे कि नेताओ की रिटायरमेंट उम्र क्या हो। ये लोग कब्र मे पाव लटकाये रहते है। फिर भी चुनाव लडेगे । इनकी उम्र क्यो न 60 या 65 तक ही सीमित की जाय।

उत्तर– विधायिका के लोग चाहे वे विधायक हो या सांसद सिर्फ नीति निर्माता होते है। कार्यान्वयन नही करते। इसका मतलब यह हुआ कि वे सिर्फ सलाहकार, समीक्षक अथवा आदेश कर्ता तक सीमित होते है। आदेश कर्ता भी वे व्यक्ति के रूप मे न होकर सिर्फ सामूहिक ही होते है। इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी योग्यता सिर्फ एक ही होती है कि वे समाज के विश्वास पात्र हों। न उम्र का कोई संबंध होता है, न ही किसी योग्यता का । उम्र तथा योग्यता उन लोगो के लिये होती है कि जिन्हे कार्यान्वयन करना हैं, नीति निर्धारण नही। जो लोग चुने जाते है, उनके लिये किसी प्रकार की योग्यता निर्धारित करना मतदाताओ के लिये एक सलाह तो हो सकती है, किन्तु बाध्यकारी नही। आपने जो कहा है, वह मतदाताओ के लिये उचित सलाह है। किन्तु ऐसा कोई कानून बनाना उचित नही। यहां तक कि कुछ राज्य सरकारो ने ऐसे निर्वाचित पंचो के लिये चौथी या आठवी पास करना अनिवार्य कर दिया है। यह भी गलत है। मेरे विचार मे वृद्ध अनुभवी लोगो का मार्ग दर्शन लेना किसी भी रूप मे गलत नही है, यदि हम ऐसा मानते है कि उनमे यह क्षमता है। उनमे योग्यता अथवा क्षमता है कि नही यह निर्णय मतदाताओ पर छोड देना चाहिये।

6रविन्द्र सिंह पत्रकार, सवाद सरोवर, गुना, म0प्र0, ज्ञान तत्व कमांक 41072

प्रश्न—ज्ञान तत्व 283 मे ओम प्रकाश मंजुल बरेली के 5 प्रश्न है । आपने उत्तर लम्बा दिया है। अहं से पीडित तलवार दंपत्ति ने यह मान कर हत्या की होगी कि धन बल पर निर्दोष छूट जायेगे। कानून तोडने से पहले अपराधी बचने के सभी रास्ते सोच लेता है। अनेक अपराधी संदेह का लाभ उठाकार बच भी जाते है। मंजुल जी को यह भी समझना चाहिये कि हत्या की नही कराई जाती है। इस हत्या मे सबसे बडी दोषी पैसे को भगवान मानने वाली समाज की इकाई है, जिसने छोटे परिवारो को वढावा देकर व्यक्ति को एकाकी कर दिया है। हेमराज का मात्र अपराध इतना ही था कि उसने एकान्त का लाभ उठाया था । कानून किसी की हत्या करने या स्वयं न्याय करने का अधिकार नही देता है।

2 आकडे झूठ नही बोलते , उनसे सच्चाई छिपाई जा सकती है। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री के रूप मे राज्य सभा से आये थे । ब्रिटेन की तरह हमारी राज्यसभा भी हाउस आफ लार्डस हो गई है। वित्त मंत्री के रूप मे उन्होने अमीरो को सुविधाए वक्श कर उनमे पद और पैसे का मोह बढाया जिससे विगत दो तीन दशको मे भ्रष्टा चारियो को संरक्षण मिला है।

कम्पनियां ही नही , बैक भी स्वैच्छा चारी हो गये है। निरक्षरो को चेक बाट कर वित्त मंत्रालय गरीबो का शोषण कर उन्हे सुविधा भोगी बना रहा है। नरेगा के पहले न्यूनतम मजदुरी जिला प्रशासन तय करता था। अब एन जी ओ शासन के रेट से भी मेहनत करने वाले को कुछ कम ही देते है। कागजो पर आंकडो की दूकानदारी घोषित करते है। यह सत्य विपक्ष जानकार भी चुप रहता है। वह केवल आंकडो के आधार पर ही सत्ता की दुर्दशा का मखौल उडाता है। आप भी इस सत्य को जानने की कोशिश करियेगा।

उत्तर– मैने मंजुल जी के आरूषि हत्या कांड संबंधी प्रश्न का जो उत्तर दिया उसकी आपने समीक्षा की हैं । मेरे विचार मे आपका यह सोच गलत है, कि आरूषि की हत्या इस उम्मीद पर की गयी कि वे धन बल पर छूट जायेगे। हत्या सरीखा जधन्य कार्य भी उस समय कानूनी अपराध नही होता जब वह आत्म सुरक्षा के लिये हो अथवा भावनावश हो। भावनाओ का मापदंड भी जरूरी होता है। यदि अपराध आत्म सुरक्षा या भावना वश भी हो तब भी उसकी बहुत सूक्ष्म विवेचना होती है। स्वार्थ वश किया गया अपराध और आत्म सुरक्षा या भावनावश किये गये अनुचित अपराध भी एक समान नही हो सकते। इसी लिये हमारा मानना है कि परिवार के किसी सदस्य की हत्या परिवार के सदस्यो द्वारा सामाजिक नियमो के बचाव मे होती है तो वह उतना गंभीर अपराध नही है, जितना किसी अन्य की हत्या का तथा स्वार्थ वश की गयी हत्या का। आत्म सुरक्षा और भावना वश किया गया अपराध भी स्वार्थ वश किये गये अपराध जितना गंभीर नही होता। आरूषी हेम राज का मामला ऐसी ही श्रेणी मे आता है। इसपर भी सोचा जाना चाहिये था। और इसलिये ही मैने लिखा कि दंड अधिक कठोर हो गया। यदि

परिवारो को संवैधानिक मान्यता दे दी जाय तो परिवारो का छोटा होना रूक सकता है। हेम राज का अपराध भी उतना कठोर दण्ड देने लायक नही था, जैसा तलवार दम्पत्ति ने दिया। किन्तु उसका कार्य भी अपराध की श्रेणी मे आता है। क्योकि उसने परिवार के पारिवारिक मामलो मे हस्तक्षेप करके अपराध किया था। कानून किसी को हत्या करने का अधिकार नही देता है। आपका यह कथन भी अर्ध सत्य है।

आपने दूसरे प्रश्न मे मनमोहन सिंह की अर्थनीति पर लिखा हैं। मनमोहन सिंह की अर्थ नीति गलत है, इससे मै सहमत हूॅ । किन्तु आपने जिस नीयत से यह प्रश्न किया है उस नीयत के प्रति मेरा समर्थन नही है। मनमोहन सिंह की अर्थनीति उस अर्थनीति से अच्छी हैं जो 91 के पहले चल रही थी और जिसमे सारे आर्थिक अधिकार भी उसी सत्ता के पास थे, जिसके पास अन्य सारे अधिकार थे। जो लोग मनमोहन सिंह की अर्थनीति को गलत समझते है, उन्हे साथ मे विकल्प भी बताना चाहिये, और यदि बिना विकल्प के कोई आलोचना की जाती है तो उसका अर्थ होता है कि वह आलोचक 91 के पूर्व की अर्थनीति का समर्थक है, जिसमे सारे अधिकार राजनेताओ तक सिमट गये थे। आपने कोई विकल्प नही दिया है। इसलिये मैने आपकी नीयत पर प्रश्न किया हैं । निरक्षरो को चेक बाटने से आपको कष्ट हुआ यह बात मेरी समझ मे नही आयी कि निरक्षर और साक्षर मे आप शिक्षितो के प्रति इतने उदार क्यो है। गरीब निरक्षर सुविधाओ का लाभ न ले सके और सारी ठेकेदारी उपर वाले लोगो की ही हो यह बात मुझे नही जची । श्रम और बुद्धि के बीच अंतर तो होगा ही किन्तु जो अंतर वर्तमान मे है वह अन्यायपूर्ण है। नरेगा जो मजदूरी तय करता है, वह गलत नही है। क्योकि वह न्यूनतम मजदूरी पर रोजगार देने को बाध्य भी है। किन्तु पहले जिला प्रशासन मजदूरी तय करता था वह एक गलत प्रक्रिया थी क्योकि वह घोषित मजदूरी दो प्रकार की मजदूरी समाज मे बनाती थी । एक थी वास्तविक जो मजदूर को बाजार मे मिलती थी और दूसरी थी कृत्रिम जो सरकार देती थी। मै उससे सहमत नही हूॅ । मै नरेगा से सहमत हूॅ । नरेगा ने बाजार मे वास्तविक मजदूरी को बढाया है और सरकार द्वारा घोषित पूर्व प्रथा लगातार श्रम का शोषण करती रही है। आप क्यो नरेगा के विरूद्ध है , यह आप स्पष्ट करियेगा। आपने यह भी लिखा है कि ज्ञान तत्व के उत्तर छोटे और सारगर्भित होने चाहिये। मै मानता हूॅ कि आप जैसे उच्च कोटि के विद्वानो के लिये ये उत्तर लम्बे हो जाते है। किन्तु आपको मै बताना चाहता हूॅ कि ज्ञान तत्व के पाठको मे आप जैसे उच्च कोटि के विद्वानो की संख्या नगण्य है, तथा सामान्य पाठको की अधिक। आप मेरी मजबूरी को समझने का प्रयास करियेगा ।

7अमर सिंह आर्य जयपुर राजस्थान ज्ञान तत्व 50805

प्रश्न–1 अभी गत दिनो विज्ञान भवन मे प्रधान मंत्री जी, सोनियां गांधी जी के साथ अल्प संख्यक समुदाय के लिये 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा कर रहे थे। दिल्ली के जाफराबाद के एक सामाजिक कार्यकर्ता डा फहीम बेग ने प्रश्न उठाया कि घोषणाए तो पहले भी बहुत हो चुकी है परन्तु उसका पैसा आज तक नही पहुचा। कहां जाता है इसकी कोई छानबीन नही होती। पैसा लोगो तक जा रहा है कि नही यह सरकार की जिम्मेदारी नही । डा बेग ने आगे कहा । मैने आपको 500 पत्र लिखे परन्तु एक का भी जवाव नही मिला । प्रधान मंत्री जी ने कहा कि आप पत्र क्यो लिखते है। इतना कहना था कि सुरक्षा गार्डो ने उस व्यक्ति को कुर्सी से खीच लिया और बोल न पाये उसके मुह को हाथ से बंद कर दिया। सोनियां तथा प्रधान मंत्री की मौजुदगी मे उनके देखते यह सब हुआ । सारा हाल जनता अवाक देखती रह गयी। मै टीवी पर यह देखकर व्यथित हो गया कि क्या यही जनतंत्र हैं ? अल्प संख्यक मंत्री का भाव यह था कि जनता शिकायत न करे । अभिजात वर्ग के राजनेता जो कहे उसे गुलामो की तरह मानते रहें । सत्ता के कार्यो पर सवाल न उठाये अन्यथा उस आवाज को दबा दिया जायेगा।

2 आज देश का युवा नशे की लत से बेहाल है। सरकार समाज तथा बेपरवाह लोग शराब पीने पर रोक का विरोध करते है दूसरी ओर शराब पीकर होने वाले अपराधो को सरकार रोकना चाहती है। स्वतंत्रता के नाम पर स्वेच्छाचार की छूट चाहते है और दुराचार बलात्कार को रोकना चाहते है। निजता के नाम पर मानवाधिकार की आड लेकर दुराचार तथा वासना का वातावरण तैयार करते है। निजता से यदि समाज को हानि हो तो क्या ऐसी निजता स्वीकार होनी चाहिये।

3 राजनीतिक दल सामप्रदायिक खतरे का 65 वर्षो से ढोल पीटते आ रहे है । समाज मूलतः साम्प्रदायिक नहीं। साम्प्रदायिकता किसी न किसी रूप मे राजनीति का परिणाम है। मुजफफर नगर का दंगा सरकार प्रायोजित है। यदि दंगो की रात कलेक्टर एस पी को बदलने के स्थान पर उत्तर प्रदेश की सरकार बदल गयी होती तो साम्प्रदायिक दंगे की असलियत

सामने आ जाती। मै उसी क्षेत्र का जन्मा हूॅ तथा शिक्षा पायी है। आजादी के समय से लेकर कभी उस क्षेत्र मे दोनो सम्प्रदायो के बीच दंगा नही हुआ। एक धार्मिक स्थान को लेकर मेरे गांव मे एक बार तनाव हुआ। मै छोटा था। ताउ महमूद खा हमारी बैठक पर आये । मेरे पिता को पूछा। वे खेतो पर गये थे। मै बुलाकर लाया । दोना साथ गये। और गांव वालो को समझा कर स्थान बदल कर रास्ते सडक हेतु जगह दी गयी। फिर कभी ऐसी नौबत नही आयी। आज भी दोनो की मिसाल दी जाती है। आज गांवो का स्वराज्य छीन लिया । सरकार का हस्तक्षेप दंगो का एक मुख्य कारण है। 24 फरवरी को मुलायम सिंह की अलीगढ मुस्लिम विश्व विधालय मे सभा थी वहा के अध्यापक व विधार्थियो ने उन्हे सुनने से इन्कार कर दिया । शायद लोग अब नेताओ क दुराचरण को पहचानने लगे है।

4 ये बात मेरी तो समझके बाहर है कि मोदी साम्प्रदायिक तथा नीतिश, मुलायम सिंह, लालू, मायावती, जय ललिता, मनमोहन, सोनिया राहुल शरद यादव आदि आदि बी जे पी को छोड सभी गैर साम्प्रदायिक है। गैर सामप्रदायिक व्यक्ति मोदी से गठजोड करते ही सम्प्रदायिक तथा उसे छोडते ही गैर साम्प्रदायिक हो जाता हैं । रामविलास पासवान उदित राज वी जे पी मे गये है। नीतिश, जय ललिता, ममता बी जे पी से बाहर के लोग उनके आचरण को कैसे परिभाषित करेगें।

5 केजरीवाल जी अचानक दिल्ली के राजनैतिक पर्दे पर उभरे और गायब हो गये किन्तु दिल्ली सरकार, केन्द्र, कांग्रेस, बीजेपी दोनो को कुछ जख्म तो दे ही गये । कुछ सुधरने की सीख दे गये। परन्तु आप पार्टी का दिल्ली की शिक्षा मे दखल किस स्वराज्य का भाव है? क्या ऐसे हाल सुधर सकते है ?

उत्तर– 1 प्रधान मंत्री जी से सोनिया जी की उपस्थिति मे डा वेग प्रश्न कर रहे थे, सूचना दे रहे थे, शिकायत कर रहे थे या भाषण दे रहे थे, इसकी जानकारी के अभाव मे गलती कहां है यह कहना संभव नही। किसी आम सभा मे कोई व्यक्ति समय लेकर और समय सीमा का ध्यान रखकर ही बोल सकता है। यदि ऐसे अवसर पर कोई व्यक्ति अपनी सीमा का उलंघन करे तो डा वेग के साथ पुलिस ने जैसा व्यवहार किया वह व्यवहार उचित था और डा वेग का गलत। जनतंत्र का यह मतलब नही जो आप निकालते है। सैकडो लोगो के बीच मे एक व्यक्ति सीमा से अधिक बोलता रहे यह बाकी लोगो के अधिकार छीनने जैसा कार्य है और इसकी सहमति नही दी जा सकती। सत्ता की कमियो पर प्रश्न उठाने का यह उचित तरीका नही था जो डा वेग ने किया । और जिसका आपने समर्थन किया। आपको इस तरह के मुददो पर व्यथित नही होना चाहिये। डा वेग ने पांच सौ पत्र लिखे । यदि कोई ब्यक्ति एक लाख पत्र लिख दे तो बिना पत्र को देखे उसके महत्व को कैसे स्वीकार किया जा सकता है।

2 शराब पीने पर किसी तरह की रोक का मै भी विरोधी हूॅ । मै जानता हूॅ कि गांधी शराब के प्रतिबंध के समर्थक थे। किन्तु इसके बाद भी मै इसका विरोधी हूॅ क्योकि शराब पीना अपराध नही है। शराब का विरोध समाज को करना चाहिये। परिवार को करना चाहिये। किन्तु सरकार को नही। गुलाम मानसिकता के लोग अपना काम तो करते नही और सारा काम सरकार से कराना चाहते हैं, इससे भ्रम फैलता है, और सरकार के उपर अनावश्यक वजन बढता है, जिसका दुष्परिणाम होता है कि सरकार शराब पर नियंत्रण जैसे सामाजिक कार्य तो करने लगती है, तथा चोरी, हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे अपराधो को नही रोक पाती। मै स्पष्ट कर दू कि मै अपराध नियंत्रण को सरकार का दायित्व मानता हूॅ और शराब वैश्या वृत्ति आदि को समाज का दायित्व मानता हूॅ। अपराध नियंत्रण मे समाज को सरकार की मदद करनी चाहिये किन्तु कभी अपराध नियंत्रण का कार्य स्वयं नही करना चाहिये । उसी तरह सरकार को शराब और वैश्या वृत्ति सरीखे कार्यो मे समाज की सहायता करनी चाहिये किन्तु कभी पहल नही करनी चाहिये। कभी कानून से प्रतिबंध तो होना ही नही चाहिये।

3 मै आपसे सहमत हूॅ कि लगभग सभी राजनैतिक दल साम्प्रदायिकता के विस्तार के पक्षधर है। इसमे न मोदी बाहर है, न सोनिया गांधी और न कोई और । मुजफ्फर नगर का दंगा प्रायोजित था यह सही है। संगठित मुसलमानो ने शुरूआत की जिसका लाभ वी जे पी ने उठाया यह भी सही है। मुलायम सिंह जी का अलीगढ विश्व विधालय मे विरोध होना साम्प्रदायिकता है न कि धर्म निरपेक्षता । मुलायम सिंह जी ने प्रारंभ मे एस पी कलेक्टर को हटाकर भूल की जिसका सुधार उन्होने बाद मे किया और उस सुधार से अलीगढ के साम्प्रदायिक मुसलमान नाराज हुए और उस नाराजगी की आप चर्चा कर रहे है यह बात मेरे समझ मे नही आयी।

4 आपने मोदी को धर्म निरपेक्ष और नीतिश लालू मुलायम मायावती जय ललिता मनमोहन सिंह आदि को साम्प्रदायिक कहा। यह बात गलत है। भारत मे साम्प्रदायिकता स्वतंत्रता के बाद हिन्दू संगठनो ने शुरू की न कि मुस्लिम संगठनो ने । स्वतंत्रता

के बाद ही हिन्दू संगठनो ने जिस तरह गांधी की हत्या की उसके बाद भी ऐसे संगठनो को धर्म निरपेक्ष आप कह सकते है, मै नही। साम्प्रदायिक नेता एक संप्रदाय से टूटकर दूसरे संप्रदाय के साथ हो जाते है। यह चर्चा का विषय नही । इस विषय पर चर्चा करने से ऐसा महसूस होता है कि आप भी किसी साम्प्रदायिक विचारधारा के पक्षधर है। सच्चाई यह है कि नीतिश कुमार की नीतियां अर्धसाम्प्रदायिक है। कांग्रेस तथा अन्य धर्म निरपेक्षो की नीतियां तीन चौथाई साम्प्रदायिक है। और संध परिवार पूरी तरह साम्प्रदायिक है। आपके उत्तर की प्रतीक्षा है।

5 यह सही है कि दिल्ली के चुनावो के परिणाम आने के बाद केजरी वाल के पक्ष मे जो बाढ आयी थी वह अब उतर गयी है, और वे अपनी मूल स्थिति पर आ गये है। यह बात भी सही है। कि केजरीवाल लगातार एक से बढकर दो तीन चार की ओर जा रहे है और नरेन्द्र मोदी की संभावनाये सौ से घटकर निन्यानवे, अन्ठानवे सन्तानवे की दिशा मे बढ रही है। मोदी के समर्थको मे कुछ चिंता का प्रकट होना इस विचार को स्पष्ट करता है। इस संबंध मे आपके क्या विचार है यह आप बताने की कृपा करे। अरविन्द केजरीवाल की पार्टी ने दिल्ली मे शिक्षा मे जो हस्तक्षेप किया वह उचित नही था। शिक्षा राज्य का विषय नही है बल्कि समाज का विषय है। यह उन्हे स्पष्ट होना चाहिये था।

8 कौशल किशोर, हाजीपुर, विहार, ज्ञान तत्व क्रमांक 24117

प्रश्न–ज्ञान तत्व अंक 166 पृष्ठ 18 पर ज्ञान हीन सक्रियता और ज्ञानवान निष्क्रियता शब्द समूह अध्ययन के उपरान्त मिले थे। विचार मंथन की दृष्टि से मैने ज्ञान तत्व अंक 228 मे लिखा था कि ज्ञानहीन सक्रियता और ज्ञान हीन निष्क्रियता के कई कारण है। जिनपर विचार किया जाना चाहिये।

ज्ञानवान तो निष्क्रिय नही रह सकता, किन्तु यदि निष्क्रियता है तो उसके भी कई कारण है। ज्ञान व्यापक अर्थ समेटे एक शब्द है। ज्ञान सांसारिकता का अनुभूत तर्क है जो अपनीअपनी बोधगम्यता का उपादान है और अवसान भी । प्रस्तुत विषयवस्तु के प्रति अपनी अभिरूचि यदि रूचि व महत्व है तो परिमाप क्या है जिससे कि सक्रियता बढे? जब तक ज्ञान हार्दिक अभियान नही होगा तब तक ज्ञानवान की निष्क्रियता बनी रहेगी। ज्ञानवान प्रयत्नपूर्वक किये गये कार्य परिणामो के आकलन से संतुष्ट और सक्रियहै। इसमे ज्ञानवान की उपेक्षा दृष्टि भी काम कर रही होती है। इसका मूल कारण कार्य पद्धति और भावना ही है। क्योकि एक तो ज्ञानवान कम होते है और ज्ञानहीन अधिक। ज्ञानवान कामनाओ से परे अर्थात निःस्वार्थ होते है और निष्काम प्रवृत्ति सांसारिकता से दूर ले जाती हे और वे निष्क्रिय रूप धारण कर लेते है। जब किसी अच्छे कार्य के अच्छे परिणाम प्रात नही होते तो वे यह सोच लेते है कि छोडो ये झंझट मेरे वश का नही। भीरूता ज्ञानवानो का कर्तब्य नही किन्तु दुर्भाग्यवश भारत मे ऐसा ही हो रहा है। दुबुद्धि ने ज्ञान को ढक लिया है। अभियान क्या चले। अभिमान ही अभिमान दिख रहा है। स्वाभिमान सोया हुआ है। स्वार्थी लोग भी शरीफ सा वेष धारण कर स्वाभिमान का गला घोट रहे है। ज्ञानवान निश्छल है तो ज्ञानहीन धूर्त । आज अधिसंख्य ज्ञानहीन अपने अनैतिक अवैध और अपराध कार्यो से मनोनुकूल परिणाम पाकर उत्साहित है और उन्हे तदनुकूल प्रोत्साहन व सहयोग भी मिलता है तो सक्रिय होना स्वाभाविक ही है। ज्ञानवान को अक्सर अपना स्वभाव परिवर्तन की सीख दी जाती है। ताकि ज्ञानहीनो का ठग अभियान जारी रहे।

आजकल छदम ज्ञानवान कहे जाने वाले भी मौजूद है,जो ज्ञानवानो के सामने एक जटिल समस्या है कि वे छदम ज्ञानवान और ज्ञानहीनो का भेद करे। वे श्रम मूल्य के शोषक और अवैध कार्य के संचालक है। सिर्फ तर्कजाल से स्वार्थ साधन किये जा रहे है। ऐसे छिपे हुए भेडिये समाज के शत्रु एक तरफ तो जनहितैषी बाते करते है, व्यवस्था परिवर्तन के समर्थक है, किन्तु समाज की दुर्ब्यवस्था के लिये उन्हे तंत्र मे ही दोष नजर आता है। अवैध कार्य से तंत्र सुधर सकता है ऐसा उनका भ्रम है। तंत्र कमजोर होगा तो लोक मजबूत, लोक बेदाग हैं । उन्हे यह नही सूझता कि भ्रष्टाचार लोक से निकलकर तंत्र तक पहुंचा है। क्या कीचड से कीचड धुलता है? तंत्र के विरूद्ध भ्रष्टाचार नियंत्रण के अभियान चलाये जा रहे है। लोक अपना भ्रष्टाचार कब दूर करेगा? लोक यदि भ्रष्ट नही होता तो तंत्र भी भ्रष्ट नही होता । आज व्यवस्था परिवर्तन की आड मे गुपचुप तरीके से तंत्र संपर्क से लाभ उठाते है। ऐसे दुमुंहे चरित्र के लोगो ने स्वयं मे एक छदम छवि बना ली है और वे दोहरा लाभ उठा रहे है। एक तरफ लोक से तो दूसरी ओर तंत्र से। व्यवस्था परिवर्तन का अभियान एक फायदेमंद सौदा के रूप मे नजर आ रहा हैं यानी जनता और सत्ता लोक तथा तंत्र दोनो को मूर्ख बनाने वाले व्यवस्था परिवर्तन के हिमायती भी मौजूद है।

ऐसे छदम ज्ञानवानो की भी स्थिति ऐसी ही होती है। अत ज्ञानहीन सक्रियता के संचालक और ज्ञानवान संचालित है। ऐसे ही कारण है कि सन 1947 ई के बाद कोई परिवर्तनकारी जनान्दोलन नही हुआ हैं अन्ना हजारे के नेतृत्व मे जनान्दोलन तो हुआ इसमे कितने ज्ञानवान थे और कितने ज्ञानहीन यह एक विचारणीय प्रश्न है । भ्रष्टाचार लोक सुधार तथा तंत्र सुधार के संगम से दूर होगा। परस्पर दोनो पूरक है। वे एक दूसरे से प्रभावित होते और करते है। लोक के सुधार के बिना तंत्र कैसे सुधरेगा। क्योकि लोकतंत्र अर्थात लोक का तंत्र है। चित्तवृत्ति जब तक प्रवृत्ति नही बन जाती तब तक समाज की चिन्ता नही करता । मानक परिभाषा देना एक अत्यन्त चुनौती पूर्ण कार्य है और उससे बडी चुनौती उस परिभाषा का पालन करना और सबसे बडी चुनौती यह है कि परिभाषा देने वाले अपनी परिभाषा पर खरे नही उतरते और अपनी सुविधानुसार उसमे परिवर्तन करते रहते है ताकि स्वयं का सुधार न करके स्वयं का हित साधन हो । ऐसे लोग अपनी ही बातो को रखने के लिये आयोजन सम्मेलन करते है।

व्यवस्था परिवर्तन के चहेता कहते है चरित्र परिवर्तन नही होगा ते क्या चरित्रहीनता से व्यवस्था बदलेगी? किसी चरित्रहीन भ्रष्ठ से प्राप्त संदेश, आदेश अथवा उपदेश परिवर्तन लायेगा? इसीलिये सामाजिक चिंतन को चरित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिये। ऐसे लोग जिनका कोई स्वयं का चरित्र नही, ऐसे ही जन ज्ञानवानो की निष्क्रियता की जड है। किसी बनिये की दूकान से परिवर्तन की आशा व्यर्थ है, न जाने कितनी दूकाने खुली हुई है। भारत मे क्रान्ति सामाजिक चिंतन व परिवर्तन तमाशा की तरह दिख रहे है। सामाजिक चिंतको कार्यकर्ताओ के चरित्र दिख रहे है पहले भी आमजन देख चुके है।

उत्तर– आपने प्रथम पाराग्राफ मे जो कुछ भी लिखा है उससे मेरी सहमति है। किन्तु दूसरे पाराग्राफ से मेरी असहमति है और तीसरे पाराग्राफ से मेरा विरोध है। दूसरे पाराग्राफ मे आपने लोक और तंत्र के संबंधो पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि तंत्र की अपेक्षा लोक अधिक भ्रष्ट है क्योकि लोक मे से ही तंत्र बनता हैं। तंत्र के विरूद्ध भ्रष्टाचार अभियान चलाना गलत है आदि आदि । मेरे विचार से आदर्श लोक तंत्र मे लोक संचालक होता है और तंत्र संचालित । संविधान बनाने मे लोक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और संविधान के आधार पर तंत्र संचालित होता है। किन्तु भारत के प्रदूषित लोकतंत्र मे तंत्र ही संविधान पर भी नियंत्रण करता है और वही उस गुलाम संविधान के आधार पर तंत्र को संचालित भी करता है। मै नही कह सकता कि ऐसी स्थिति मे तंत्र को संचालक कहा जाय या संचालित । मेरे विचार मे तंत्र संचालक है और लोक संचालित । क्योकि लोक के सारे अधिकार तंत्र तय करता हैं और अपने सारे अधिकार भी तंत्र ही तय करता है। लोक को ऐसा कोई अधिकार नही जिसे तंत्र नियंत्रित न करे । दूसरी ओर तंत्र को ऐसा कोई अधिकार नही जिसे लोक नियंत्रित करे। एक वोट देने का अधिकार लोक के पास है और उस वोट के द्वारा वह अपना मालिक चुन लेता है जो लोक को पांच वर्षो तक मालिक के रूप मे संचालित करता रहता है। लोक और तंत्र के इस संबंध को बदलने का प्रयास व्यवस्था परिवर्तन है जो लोक स्वराज्य मंच जैसी अनेक संस्थाए कर रही है। यदि इनके अतिरिक्त कोइ और कार्य व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हो रहा है तो वह आपके लिये भी चिंता का विषय होना चाहिये और हमारे लिये भी। लोक और तंत्र एक दूसरे के पूरक होने चाहिये परन्तु है नही। क्योकि दोनो के पूरक होने मे संविधान पुल का काम करता है । जिसपर वर्तमान मे तंत्र ने नियंत्रण कर रखा है। अतः मेरे विचार से व्यक्ति दोषी नही है । समाज भी दोषी नही है।व्यक्ति और समाज पर तंत्र का पडता हुआ प्रभाव दोषी है।

आपने तीसरे पाराग्राफ मे चरित्र को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इस पाराग्राफ मे आपने व्यवस्था परिवर्तन मे लगी इकाइयो के चरित्र संबंधी कथन को जोडते हुए यह लिखा है कि किसी बनिये की दुकान से परिवर्तन की आशा करना व्यर्थ है। मुझे यह बात इसलिये कटाक्ष के रूप मे लगी क्योकि मै व्यवस्था परिवर्तन का पक्षधर हूँ। राजनीति मे राजनेताओ के चरित्र को महत्व नही देता और जन्म से बनिया हूँ। व्यक्ति तीन प्रकार के होते है। 1 सामाजिक 2 असामाजिक 3 समाज विरोधी । असामाजिक लोगो के चरित्र निर्माण का कार्य समाज करता है। समाज विरोधी तत्वो पर नियंत्रण का कार्य तंत्र का होता है जिसे हम अभी सरकार कहते है। यह तंत्र भी समाज मे से ही समाज के द्वारा बनाया जाता है। इस तंत्र का कार्य न समाज पर नियंत्रण का है न असामाजिक तत्वो पर नियत्रण का । सिर्फ इसका एक ही कार्य है और वह है समाज विरोधी तत्वो पर नियंत्रण का। चरित्र निर्माण समाज का काम है। सरकार का नही। किन्तु सरकार सामाजिक लोगो पर भी नियंत्रण करना चाहती है, असामाजिक लोगो पर भी । जिसके परिणाम स्वरूप समाज विरोधी तत्वो पर नियंत्रण का उसका कार्य पिछड जाता है। राज्य अथवा सरकार की इस दिशा को बदल कर समाज विरोधी तत्वो तक सीमित करने का

कार्य ही व्यवस्था परिवर्तन है। सरकार या राजनीति से जुडे लोग इसे व्यवसाय समझकर करने लगे हैं । व्यवस्था परिवर्तन के कार्य करने के लिये आदर्श स्थिति मे ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप मे कार्य विभाजन हुआ। सरकार का काम करने वालो को क्षत्रिय कहा गया। विचारो का कार्य करने वाले ब्राम्हण कहे गये। व्यापार करने वाले वैश्य कहे गये । और श्रम जीवियो को शुद्र कहा गया। यह वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, जन्म के आधार पर नही। जब इसमे विकृति आयी और इसे बुद्धिजीवियो ने जन्म के आधार पर कर दिया तो इससे अव्यवस्था पैदा हुई और सभी वर्णो मे सब प्रकार के लोग होने लगे। जब सरकार अर्थात क्षत्रिय ने शेष तीनो वर्णो को गुलाम बना दिया तो आवश्यक है कि तीनो वर्ण चाहे वे जन्म से हो या कर्म से इस संकट को दूर करने के लिये एक होकर काम करे। यही काम पूर्व मे गांधी ने भी किया था और यही काम वर्तमान मे भी हो रहाहै। चाहे वह किसी बनिये की दुकान से ही क्यो न हो रहा हो। बनिया की दुकान को आपने जिस तरह तिरस्कृत किया वह मेरी समझ से परे है। जन्म से बनिया कर्म से ब्राम्हण बन सकता है। और यदि आवश्यक हो तो आपात काल मे कर्म का बनिया भी व्यवस्था परिवर्तन का कार्य कर सकता है। इसमे किसी को कोई कष्ट नही होना चाहिये। आपने बहुत गंभीर पत्र लिखा है। लम्बा होने के कारण मैने उसे संक्षिप्त किया है। आशा है कि आप इस पर भी तथा अन्य विषयो पर भी अपनी टिप्पणी लिखते रहेंगे।

उत्तरार्ध

निवेदन– लोक सभा चुनावो के बाद सरकार चाहे किसी की बने । किन्तु लोक स्वराज्य की दिशा मे कोई गंभीर प्रगति की कोई संभावना नही है। लोक स्वराज्य मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा बैगलोर कर्नाटक, तथा महा सचिव रमेश कुमार चौबे पटना विहार, और व्यवस्था परिवर्तन अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य पंकज ऋषिकेश हरिद्वार तथा महा सचिव छवील सिंह जी सिसोदिया पिलखुआ उत्तर प्रदेश ने श्री ओम प्रकाश जी दुबे, नोयडा उत्तर प्रदेश, तथा ईश्वर दयाल जी, नालंदा विहार, की सहमति से 13 जून 2014 से 22 जून 2014 तक जंतर मंतर दिल्ली मे एक धरना देने की योजना बनाई है। इस धरने मे चार मांगे रखी जायेगी। 1 संविधान मे परिवार, गांव, जिला के अधिकारो की सूची डालना । 2 राइट टू रिकाल का कानून बनाना । 3 लोक संसद बनाना। 4 प्रत्येक नागरिक को दो हजार मूल रूपया प्रति व्यक्ति, प्रति माह, जीवन भत्ता देना। इन चार मांगो का क्रम इसी तरह है तथा महत्व भी इसी क्रम से है। इस धरने से एक राष्ट्र व्यापी आंदोलन की शुरूआत हो रही है। इस धरने मे सभी दलो को आमत्रित किया जायेगा। इस धरने मे देश भर के अपने साथियों को अपनी अपनी सुविधा अनुसार शामिल होना चाहिये। यदि कोई साथी इन तीथियो मे से किन्ही एक दो दिनो के लिये भी इन्ही मांगो पर अपने क्षेत्र मे कोई धरना आयोजित करते है तो हमे बहुत खुशी होगी। इन चारो मांगो का विस्तृत विवरण ज्ञान तत्व मे तो जायेगा ही। सरकार को भी धरने के समय बताया जायेगा। आप यदि धरने के लिये कुछ दिनो के लिये भी आते है तो दिल्ली मे आपके निवास और भोजन की व्यवस्था दिल्ली के कार्यकर्ताओ की टीम करेगी।